

the disposal of the Maharashtra Government by the Central Government for the development of Ambar Char-kha during 1960-61?

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): A sum of Rs. 17,07900 has been tentatively allocated for the State Khadi & Village Industries Board for the implementation of the Ambar Char-kha Programme during that year.

सिक्किम में रेडियो स्टेशन

१६. { श्री भक्त वर्शन :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम में रेडियो स्टेशन की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केलकर) : इस बात की अभी खोज की जा रही है कि सिक्किम और उसके पास के पहाड़ी इलाकों के लिये रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाय ऐसी आशा की जाती है कि जगह का निर्णय अन्तिम रूप से इस महीने के अन्त तक हो जायेगा ।

श्रीषधि का कारखाना

२०. { श्री भक्त वर्शन :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री कोटियान :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीषधि का कारखाना खोलने तथा श्रीषधियों के पीधे उगाने के श्रीषधीय फार्म स्थापित करने की प्रत्येक योजना के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : श्रीषधि के कारखाने—मास्को के मेसर्स टेक्नो-एक्सपोर्ट के साथ जून, १९६० में की गई सविदाओं के अनुसार कीटाणुनाशक एवं संश्लेषित श्रीषधियों, शल्य चिकित्सा के औजारों तथा वनस्पति रसायन जैसी श्रीषधियाँ बनाने की चार प्रायोजनाओं के बारे में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्टें अप्रैल-जून, १९६१ तक मिल जाने की आशा है ।

श्रीषधीय फार्म—जिन राज्य सरकारों से श्रीषधियों में काम आने वाले पीधों की खेती करने की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा उनकी खेती जल्दी से जल्दी कब तक शुरू करने और आवश्यक मात्रा में उनको उपलब्ध कराने की तारीख बताने के बारे में निवेदन किया गया था, उनमें से कुछ के पास से जो सामग्री प्राप्त हुई वह वनस्पति रसायन की उप-समिति के सामने विचार करने के लिये रख दी गई है । अन्य राज्य सरकारों से सामग्री प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा है ।

तिब्बती शरणार्थी

२१. { श्री भक्त वर्शन :
श्री प्र० गं० देव :
श्री हरिश्चन्द्र भायूर :
श्री प्र० कं० देव :
श्री अजित सिंह सरहठी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री बोडियार :
श्री सीमजी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री डामर :
श्री मधुसूदन राव :
श्री कोरटकर :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या प्रधान मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों :

(क) १ जून, १९६० से अब तक

कितने तिब्बतियों ने भारत में शरण ली है ;

(ख) कितने तिब्बती प्रतिमास उत्तरी सीमा पर स्थित किन-किन दरों से होकर भारत आये ;

(ग) कितने तिब्बती किन किन दरों से होकर अब तक तिब्बत वापस जा चुके हैं ;

(घ) तिब्बती शरणार्थी कहां कहां रखे गये हैं और प्रत्येक स्थान पर उनकी संख्या कितनी है ;

(ङ) तिब्बत में विधि तथा व्यवस्था बिगड़ने के पश्चात् अब तक कुल कितने तिब्बतियों ने भारत में शरण ली है ; और

(च) इनमें से कितने तिब्बती अब तक फिर से बसाये जा चुके हैं ?

प्रधान मंत्री तथा बंदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १ जून से १५ अक्टूबर, १९६० तक ७६५४ तिब्बती लोगों ने भारत में शरण ली है ।

(ख)	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर (१५ तारीख तक)
नेफा	३८०	१२०	२०५	२४७	५२
उत्तर प्रदेश	१६१	३४७	२१२	१३०	—
लद्दाख	२२	१७३	७३	७६	१०
हिमाचल प्रदेश	६०४	३८६	—	४	३१
पंजाब	४२७	—	—	—	—
सिक्किम	४३५	५३	१०२	३३२५	७६

जिन जिन दरों से उन्होंने प्रवेश किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :

नेफा	कारपोतसांग, लहाला, तुलुंग, निलाकाला ।
उत्तर प्रदेश	लिपलेख, लिम्पिया, नेलंग ।
लद्दाख	जराला, चारदिगला, छांगला
सिक्किम	नथूला, जेलेपला, कोंगरासा, डोंगक्याला, थांकारला ।
हिमाचल प्रदेश	शिपकिला, नेसांग ।

यह कहना संभव नहीं है कि प्रत्येक दरों से होकर आने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी कितनी है ।

(ग) जो तिब्बती शरणार्थी तिब्बत को वापस चले गये हैं, उनकी संख्या के बारे में कोई सूचना सुलभ नहीं है ।

(घ) फिनहाल तिब्बती शरणार्थी इस

प्रकार बंटे हुये हैं :

पंजाब	२५४८
हिमाचल प्रदेश	१११३
सिक्किम	४२२१
पश्चिम बंगाल	३३८३
नेफा	१५५८

जम्मू और काश्मीर	८००
उत्तर प्रदेश	७००
बिहार	६३१
लद्दाख	१३२५

(इ) मार्च, १९५६ से अक्टूबर, १९६० तक २४,४८० तिब्बती भारत में भाये हैं।

(च) भालुकपुंग, नेफा में लगभग १००० शरणार्थी बसाये जा रहे हैं। ३००० और शरणार्थी नैसूर राज्य की भूमि पर बसाये जायेंगे। शेष सड़क निर्माण, जंगलात और दस्तकारी का काम कर रहे हैं।

Wage Boards

22. { Shri Ram Krishan Gupta:
Shri S. M. Banerjee:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 520 on the 18th August, 1960 and state the nature of steps taken so far for the appointment of three separate wage boards for tea, coffee and rubber plantations?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): The Industrial Committee on Plantations at its meeting held on the 9th November 1960, recommended change in the composition of the Tea Wage Board. Further action is being taken accordingly.

Bonus Commission

23. { Shri Ram Krishan Gupta:
Shri D. C. Sharma:
Shri T. B. Vittal Rao:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 353 on the 12th August, 1960 and state the nature of progress made so far in appointing a Bonus Commission?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): The matter is still under consideration.

Evacuee Agricultural Lands in Punjab

24. Shri Ram Krishan Gupta: Will the Minister of Rehabilitation and Minority Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1975 on the 2nd September, 1960 and state:

(a) whether Government have since examined the allotment of evacuee agricultural land to the remaining cultural and religious institutions in Punjab which have not started functioning as yet; and

(b) if so, the action taken in regard?

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri P. S. Naskar): (a) and (b). The examination is continuing. Cases of 117 institutions are still pending for review by the Punjab Government.

Reclassification of Government Quarters

25. Shrimati Ila Palchoudhuri: Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government residential accommodation in Delhi has recently been upgraded and reclassified;

(b) if so, details thereof;

(c) whether it is also a fact that as a result of this upgrading and reclassification hundreds of Government employees living in various Government quarters for years will have to shift to lower grade quarters situated far off from their present places of residence and will thus be put to various hardships;

(d) if so, whether Government have given any consideration to this aspect of the matter; and

(e) what steps have been taken or are proposed to be taken to ease the situation?